









# संपादकीय

## शराब नीति में हेरा-फेरी

आम आदमी पार्टी (आप) के क्रियाकलाप पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट अंतत-दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख दी गई। कुल चौदह मामलों पर कैग ने रिपोर्ट तैयार की हैं, लेकिन जिस रिपोर्ट पर सबकी नजर लगी थीं, वह आवाकारी नीति के संबंध में है। इस रिपोर्ट में शराब नीति को लेकर कोई व्यवस्था जितनी तरह की लापरवाहियां बरत सकती हैं, जितनी तरह की अनियमितताएं कर सकती हैं, और विभिन्न हित समझौतों के लिए भ्रष्टाचार की जितनी गुंजाइशें छोड़ी जा सकती हैं, उन सबका उल्लेख किया गया है। पुरानी नीति की प्रक्रियागत खामियों को दूर करने के लिए ही नई नीति का मसौदा तैयार किया था लेकिन नई नीति के क्रियाव्ययन में विशेषज्ञ समिति के अंकेक सुझावों को दरकिनार किया गया। दिल्ली में शराब वितरण केंद्रों की न केवल संख्या बढ़ा दी गई, बल्कि वितरण उन क्षेत्रों में भी पहुंचा दिया गया जहां पहले प्रतिबंधित था यानी स्कूल और आवासीय परिसरों के निकट। उत्पादन और वितरण की एजेंसियों का भी मनमाने ढंग से चयन किया गया। उन संस्थाओं को ठेके दे दिए गए जो पात्रता नहीं रखती थीं और रखती भी थीं तो उन्हें जरुरत से ज्यादा खुदरा विक्रय केंद्र आवंटित कर दिए गए। रिपोर्ट में यह उल्लेख स्पष्ट है कि शराब नीति में हेरा-फेरी और उसके क्रियाव्ययन में जो तौर-तरीके अपनाए गए उनके चलते लगभग दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ। यह तभी हो सकता है, जब नुकसान की राशि का कुछ न कुछ हिस्सा उन लोगों के पास पहुंचा हो जिन्होंने नुकसान होने दिया और इसी ने ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के लिए जांच की स्थितियां तैयार कीं जिसके कारण तबके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा। यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेज दी गई है। उसकी रिपोर्ट मिलने पर शेष स्थितियां उजागर होंगी। लेकिन आप की सरकार अपने ऊँचे-ऊँचे वादों, विचारों के पैमानों पर असफल हुई और दुखद यह है कि पराजय के बाद भी उसके नेताओं ने सबक नहीं लिया है। वे शुद्ध राजनीति पर लौटें की बजाय हांगामा छड़ा करने में अब भी ज्यादा भरोसा किए हुए हैं।

# आलेख वैश्विक राजनीति में तरकी पसंदगी का दौर खत्म...

श्रुति व्यास

दुनिया रूढिवाद के सैलाब में डूब-उत्तरा रही है। मध्यमार्गी बेचरों हो चले हैं। वे मध्य-दक्षिणपंथियों और लोकलभावनवादी दक्षिणपंथियों से पिट रहे हैं। जर्मनी इस सैलाब का सबसे नया शिकार है। वहां की मध्य-दक्षिणपंथी क्रिस्तियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी (सीडीयू) के नेता फ्रीड्रेक मर्टज़ का देश का अगला चांसलर बनना तय है। हालांकि मतदाताओं का दक्षिणपंथियों की ओर झुकाव अनुमानों से कम है, फिर भी यह जबरदस्त है। रूढिवादियों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संकल्प लिया था कि उनसे अधिक दक्षिणपंथी कोई भी दल चुनावों में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। अब यह साफ है कि वे अपने संकल्प को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रूढिवादी सीडीयू/सीएसयू ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की है। और अति-दक्षिणपंथी एफडी दूसरे स्थान पर रही है। लेकिन जर्मनी के ये नतीजे न तो आश्वर्यजनक हैं और ना ही धक्का पहुंचाने वाले हैं। सारी दुनिया में निराशा, मोहर्भंग और सार्वभौम मूल्यों के प्रति बगावत का माहौल है। इससे उग्र-दक्षिणपंथी और व्यवस्था-विरोधी दलों की ताकत में ज़िजाफ़ा हुआ है। स्थापित राजनीति को लेकर निराशा और मायूसी है, विशेषकर युवाओं में। अध्ययनों और रायशुमारियों में दावा किया गया है कि युवा आजादी (अर्थात् उदारवाद) की बजाए अंकुशों (यानि रूढिवादिता) के अधिक पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था ग्लोकलाईटिस द्वारा 2024 में किए गए अध्ययन से पता लगता है कि 2014 से 2023 के बीच, कुल मिलाकर दुनिया अधिक उदारवादी बनी। हालांकि वह इसके साथ-साथ अधिक निराशावादी भी हो गई थी। इसके नतीजा यह हुआ कि सभी महाद्वीपों में उग्र-दक्षिणपंथी मतदाताओं की छवि बदल रही है, और अति दक्षिणपंथ बने थे। तब बनाने की राजकुमारों था लेकिन चले गए। हुआ है कि की टीम न स्थायी बन नेताओं का या हाशिए टीम बना बदली हुई चेहरे भी उल्लिए बिहार डॉक्टर जा कहा है कि हो गई है, तो राहुल न बात पूरी तरह है कि के अंदराजा कोर टीम कराने, आ

हारशकर व्यास

गांधी 35 साल का उम्र म 2004 म सासंबंधित से यानी पिछले 20 साल से अपनी टीम कोशिश में हैं। एक बार उन्होंने 2009 की टीम बनाई थी, सबको मंत्री बनाया उनमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस छोड़ कर परंतु उनकी इस राजनीति का नतीजा यह सेनियर गांधी की टीम बनाम राहुल गांधी यानी पुराने और नए नेताओं का झगड़ा। अब जबकि कांग्रेस के ज्यादातर पुराने या तो निधन हो गया है या वे रिटायर में चले गए हैं तो राहुल गांधी फिर नहीं रहे हैं। इस बार उनकी विचारधारा है, राजनीतिक लाइन भी अलग है और नेतृत्व में बदल गया है। उनकी राजनीति को समझाने वाले कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता, जैसा गान्धी मिश्र के बहुत करीबी रहे नेता वामपंथी राजनीति देश में लगभग खत्म करे करेल के अलावा अगर वह कहीं बची रहे गांधी की टीम में बची है। पता नहीं यह आपका आपह से सही है या नहीं लेकिन इतना दिलचस्पी वामपंथी विचारधारा से जुड़े या एनजीआर में काम करने वाले युवा राहुल गांधी वाले में जुड़े हैं। खुद राहुल गांधी जाति गणतान्त्रिक रक्षण की सीमा 50 हजार से ज्यादा करने

आबादी के अनुपात म राजनातिक व प्रशासनिक पद देने आदि के विचार में काम कर रहे हैं। अपनी इसी समझ में वे टीम चुन रहे हैं। नेताओं की योग्यता, उनकी क्षमता, राजनीतिक अनुभव, जनता के साथ संपर्क आदि को दरकिनार करके वे उन लोगों को संगठन में आगे बढ़ा रहे हैं, जिन लोगों का विचार है कि आरक्षण की सीमा 75 फीसदी होनी चाहिए। पर्टियों के संगठन के पद जाति व धर्म के आधार पर भरे जाने चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ओबीसी, दलित, आदिवासी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी सोच में उहोंने 11 केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कराई है। इनमें आठ नेता ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सभी नेता स्वाभाविक प्रक्रिया से निकल कर ऊपर तक पहुंचे हैं और किसी पूर्वाग्रह की वजह से पहले उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी। दो प्रदेशों में पिछड़ा और दलित अध्यक्ष बनाने के बाद 11 केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति को देख कर लग रहा है कि कैसे ऐंडम तरीके से नेता चुने जा सकते हैं और उहें जिम्मेदारी दी जा सकती है। नई नियुक्तियों में कोई तारतम्य नहीं दिख रहा है। तेलुगू भाषी व्यक्ति को झारखंड और कन्नड़ भाषी व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाने के पीछे क्या सोच हो सकती है, यह कोई नहीं बता सकता है। अब तक परदे के पीछे से काम कर रहे लोगों को

राजनीति के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में नाना पटोले अध्यक्ष बने तो बाकी सारे नेता हाशिए में डाल दिए गए। पटोले खुद ही सीपीएम दावेदार हो गए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ थे और अब जीतू पटवारी हैं। छत्तीसगढ़ में जो हैं सो भूपेश बघेल हैं और हरियाणा में सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्हा के हवाले था। तेलंगाना के सारे फैसले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हवाले छोड़े गए हैं तो हिमाचल प्रदेश में सुखिंचिंदर सिंह सुकन्हू को ऐसी ताकत दी गई कि वीरभद्र सिंह का परिवार नाराज हुआ। प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या प्रभारी इनके अलावा प्रदेश की राजनीति में किसी की नहीं चलती है। कोई स्वतंत्र फोटोबैक नहीं ली जाती है। अभी तक यह सिस्टम चल रहा है कि आगे प्रदेश का कोई नेता इन तीन के खिलाफ शिकायत करे तो घूम फिर कर वह शिकायत इन्हीं के पास पहुंच जाती है। राहुल अपनी कोर टीम के सदस्यों को फील्ड की राजनीति के लिए भेज रहे हैं और उनके अलावा मल्लिकार्जुन खडगे या प्रियंका गांधी वाड़ा के प्रति निजी निष्ठा वालों को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। इससे दूसरी लाइन खड़ी नहीं होगी। स्वाभाविक राजनीति से जो नेता निकले हैं उनकी बड़ी तादाद अब भी है। कांग्रेस उन्हीं के दम पर भाजपा को चुनौती दे सकती है। लगभग हर राज्य में कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं।

# हमेशा बना रहता मातृभाषा का महत्व....

सुनील कुमार महला

हर साल फरवरी में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा का मतलब है, ऐसी भाषा, जिसे हम जन्म लेने के बाद सबसे पहले सीखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा थी है, 'है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।' सरल शब्दों में कहें, तो मातृभाषा की जगह दुनिया की कोई भाषा नहीं ले सकती। यही हमारी क्षमताओं को अच्छी तरह से निखारती है, जिसके कारण मातृभाषा में ही हर बच्चेको शिक्षित करने की बात बार-बार कही जाती है। दक्षिण अमेरिकी क्रांति के महानायक नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं, जिसे वह समझता है, तो वह बात उसके दिमाग में बसती है और, अगर आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं, तो वह उसके दिल तक जाती है। सच यही है कि मातृभाषा हमारी असली पहचान है। भारत को अगर एकता के सूत्र में बांधना है, तो हमें अपनी मातृभाषा को उचित सम्मान देना ही होगा, साथ ही, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व की अनुभूति भी करनी होगी। मातृभाषा से ही हमारे राष्ट्र और हारआध न कहा है- 'क्स नज़ साय भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहिं उर में उगा। मातृभाषा का महत्व हर वक्त बना रहता है। सैयद अमीर अली मीर ने कभी कहा था, देश में मातृभाषा के बदलने का परिणाम यह होता है कि नागरिक का आत्मगौरव नष्ट हो जाता है, जिससे देश का जातित्व गुण मिट जाता है। सच तो यह है कि मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। यह मातृभाषा ही है, जिसके माध्यम से हम भावों की अभिव्यक्ति और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देशप्रेम की भावना संचारित करती है। यह सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। यही कारण है कि प्रायः सभी समाज अपनी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाते हैं। हमारे यहां भी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर खास जोर दिया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि नौनिहालों को मातृभाषा में ही शिक्षित करना पर्यादेमंद है। आज जब दुनिया के तमाम देश अपनी-अपनी भाषा में शोध-अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमें भी

A photograph showing a young girl with dark hair in braids, wearing a headband with colorful beads, smiling at the camera. She is holding a small slate with the text "ਕ ਅ ਮਧ ਦ ਅ ਫੁਜ" written on it. Standing next to her is an older woman wearing a bright red sari with gold embroidery and several silver bangles on her wrists. The woman is also smiling. The background is a blurred outdoor setting.

मातृभाषा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसमें बुनियादी शिक्षा-दीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें इसी राह पर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। दशकों से हम सुनते आए हैं कि मातृभाषा में शिक्षा से ही किसी छात्र की प्रतिभा का तेज़ी से विकास होता है। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाबजूद हमारे देश में ऐसा संभव नहीं दिखता। एक तो पढ़ाई के माध्यम (भाषा) की समस्या और उससे भी ज्यादा 'दोहरी शिक्षा व्यवस्था'! एक तरफ गांव और शहर के गरीबों या आम मेहनतकश लोगों के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम वाले सरकारी या गैर-सरकारी स्कूल और दूसरी तरफ अमीरों, अफसरों और बड़े नेताओं के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों द्वारा स्कूल बनाये जाते हैं। जबकि, हम प्रधानमंत्री कहते हैं, 'मातृभाषा में शिक्षा भारत में छात्रों के लिए न्याय के एक नये रूप की शुरूआत है, यह सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है' उनकी इस सोच में कोई समस्या नहीं बर्ती रखी जा सकती है। यह धरातल पर उतरे। सबाल कि पूरे देश में मातृभाषा में शिक्षा वाले कितने सरकारी स्कूल खोले गए और कितने बंद हुए? हमारे माननीयों बच्चों को किन स्कूलों में शिक्षा मिल रही है? वे किस भाषा में शिक्षित हो रही हैं?

हैं ? किन्तु गणमान्य लोगों के परिवारों के बच्चे मातृभाषा में या सरकारी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं ? किन्तु ऐसे गणमान्य लोग हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षित हो रहे हैं ? बेहतर होगा, सरकारी स्तर पर ये आंकड़े प्रकाशित किए जाएं। कहे का मतलब है कि जब तक 'दोहरी शिक्षा-व्यवस्था' खत्म नहीं की जाती, तब तक मातृभाषा में शिक्षा देने का सपना हकीकत नहीं बन सकता। हमारे गांव में अंग्रेजी को लेकर ऐसी दीवानगी है कि हिंदी के वाक्यों में जब तक अंग्रेजी शब्द न शामिल किए जाएं, मानो ज्ञान का पदार्पण ही नहीं होता है। झगड़े का तापमान भी अंग्रेजी के शब्दों की अधिकता से नापी जाती है। अब तो शराबबंदी है, वरना दूसरे पैग से ही अंग्रेजी मातृभाषा का स्थान पा लेती थी। मैथिली विषय के प्रोफेसर के घर अंग्रेजी का अखबार रोज आता है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ अमरनाथ झा की कही बात, जो कभी किसी ने सुनायी थी, याद आ रही है—झा साहेब जब किसी भाषा में बोलते थे, तो वह दूसरी भाषा के शब्द उसमें प्रयोग नहीं करते थे। एक बार हिंदी के एक प्रसिद्ध कथाकार ने उनसे अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात की।







## 'गति' के जरिए ही प्रदेश सरकार 'ज्ञान' के लिए लक्ष्य को अर्जित करेगी : ओपी चौधरी

रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2025-2026 के लिए प्रस्तुत बजट के प्रमुख प्रवाचनों और घोषणाओं पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं व पैनलिस्ट्स के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष के बजट पर हमारा फोकस लड़ाई (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर था, जबकि इस बार बजट की थीम ब्रॉड (गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग आर्कस्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इण्डस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित है। 'गति' के जरिए ही प्रदेश सरकार 'ज्ञान' के लिए लक्ष्य को अर्जित करेगी।

प्रदेश के वित्त मंत्री चौधरी ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रवक्ताओं से चर्चा के दौरान बताया कि बजट की थीम 'गति' के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना, मोबाइल टार्क योजना, नवोत्थान योजना, रिपोर्ड योजना, गृहप्रवेश समान योजना, गवर्नेंस फेलोशिप, सिवान केय योजना, सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और एसएसआई का कार्यान्वयन



वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने वर्ष 2025-2026 के लिए प्रस्तुत बजट के प्रमुख प्रवाचनों और घोषणाओं पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं व पैनलिस्ट्स के साथ विस्तार से वर्षा की

विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे संकल्प को दुड़ाता प्रदान करेगी। ओपी चौधरी ने बजट में की गई बड़ी घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुराने केस में 25 हजार रु. से कम वैट वालों को माफी दी गई है। इसी प्रकार 15 हजार रु. मासिक आय वाले अब प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रबोधित 10 नई योजनाएँ मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना, मोबाइल टार्क योजना, नवोत्थान योजना, रिपोर्ड योजना, गृहप्रवेश समान योजना, गवर्नेंस फेलोशिप, सिवान केय योजना, सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और एसएसआई का कार्यान्वयन

प्रदेश के वित्त मंत्री चौधरी ने भाजपा को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रवक्ताओं से चर्चा के दौरान बताया कि बजट की थीम 'गति' के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना, मोबाइल टार्क योजना, नवोत्थान योजना, रिपोर्ड योजना, गृहप्रवेश समान योजना, गवर्नेंस फेलोशिप, सिवान केय योजना, सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और एसएसआई का कार्यान्वयन

## बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण, MSME को मिलेगा नया आयाम : सांसद बृजमोहन अग्रवाल

अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पारंपरिक उद्योगों का विकास आवश्यक : सांसद बृजमोहन

रायपुर (विश्व परिवार)। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, समृद्ध भारत के साथे को साकार करने में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (स्ल्यूस) का सशक्तिपूर्ण एक कदम साबित हो रहा है। स्टेटअंग्रेज के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से अग्रे बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सुनित हो रहे हैं। ऐसे में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कहना है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जो मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफिशिया, रायपुर रीजन द्वारा



आयोजित मेगा स्ल्यूस आउटरीच कैम्प में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कहना है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जो मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफिशिया, रायपुर रीजन द्वारा

का संवेदनशील दृष्टिकोण परिलक्षित हो रहा है। ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट प्रदेश सरकार के कार्यों के प्रति संज्ञादारी को भी प्रदर्शित करता है। सुशासन के संकल्पों को तकनीक के सहारे धारातल पर साकार किया जाएगा। ओपी चौधरी ने प्रवक्ताओं व पैनलिस्ट्स से बजट प्रस्ताव की सभी योजनाओं पर घोषणाओं के बारे बिंदु को आम जन तक ले जाने की ओपी चौधरी की।

मीडिया विभाग ने अपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जनहित हेतु शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए शाल, श्रीफल, मोमेंटो से सम्मान किया।

इस अवसर पर प्रदेश मीडिया समूह भारतीय अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, केंद्रानाथ गुप्ता, नलिनीश ठोकरे, अमित साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

इस अवसर पर शाल, श्रीफल, मोमेंटो से दी जाएगी। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बैंकों के अवसरों के द्वारा खोलने जर रहा है। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एक फोकस किया गया है जिससे प्रदेश सरकार लगाने वाले बैंक में 1 रुपए की दूर भी एक

उद्योगों के लिए प्रबोधित होता है। उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साहू, रविंद्र गुर्जे, पांडे, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष समेश ताकुर, मीडिया पैनलिस्ट डॉ. किरण बंगेल, निश्चिकात पांडे, सुनील चौधरी, वासु, हेमंत पाणिग्रही, उज्जवल दीपक, रायपुर शहर जिला उपाध्यक्ष अकबर अली उपस्थित थे।

उद्योगों को निवासित करने के लिए घोषित 10 नई योजनाएँ साहू, राजीव चक्रवर्ती, अमरजीत सिंह छाड़ा, प्रवीन साह